भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2538

(जिसका उत्तर मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2014 को दिया गया)

<u>एम.डी.पी. फर्मों को बढ़ावा दिया जाना</u>

2538. डा. संजय सिंह :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप (एम.डी.पी.) फर्मों की अवधारणा को बढ़ावा देने के संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) मल्टी डिसिप्लिनरी परिपाटी को बढ़ावा दिए जाने की वैधानिक मंशा के बावजूद क्या मंत्रालय द्वारा इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की एम.डी.पी. को बढ़ावा देने की कोई योजना है क्योंकि सीमित दायित्व साझेदारी (एल.एल.पी.) को प्रभावी व्यवसायिक साधन बनाने हेतु एम.डी.पी. की आवश्यकता है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ग) : भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएआई) के मध्य उनके सदस्यों के बीच बहु-विषयक भागीदारियों (एमडीपी) की अनुमति देने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने के संबंध में विचार-विमर्श अनिर्णित रहे। अत:, एमडीपी की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के प्रयास अभी जल्दबाजी होंगे।

(घ) और (ड.) : प्रश्न नहीं उठता।

*****